शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 1 – 8 सितम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

# सूचना एकत्रित की जा रही है इस जवाब से विपक्ष को तो शान्त किया जा सकता है जनता को नहीं

**शिमला/शैल।** सुक्खू सरकार पहले दिन से ही वित्तीय संकट में चल रही है इसीलिये इस सरकार को पदभार संभालते ही जनवरी से मार्च तक ही कर्ज लेना पड़ गया था। इस कर्ज के आंकड़े डॉ. राजीव बिंदल ने आर. टी.आई. के माध्यम से जारी किये थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की जनता को पदभार संभालते ही कठिन वित्तीय स्थिति की चेतावनी भी दे दी थी। मुख्यमंत्री इस वित्तीय स्थिति के लिये पूर्व की सरकार को दोषी करार देते आ रहे हैं। इस कठिन वित्तीय स्थिति से बाहर निकलने के लिये इस सरकार ने जहां कहीं भी संभव था वहां पर टैक्स लगाने का काम किया है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हर सुविधा का शुल्क बढ़ाया है। डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के दामों में भी दोगुनी से ज्यादा कीमत बढ़ाई है। यह जानकारी सदन में एक सवाल के जवाब में आयी है। इस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम छः माह में लिये फैसले बदल दिये थे। इन छः माह में खोले गये सारे संस्थान बंद कर दिये गये थे। सरकार ने अपनी ओर से वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये हर संभव प्रयास किया है। लेकिन जितना प्रयास किया गया उसी अनुपात में स्थिति बद से बदतर होती चली गयी और इसी स्थिति के कारण आज हर कर्मचारी को तय समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है और न ही पैन्शनरों को समय पर पैन्शन का भुगतान हो पा रहा है। जबकि हर माह औसतन एक हजार करोड़ का कर्ज यह सरकार लेती आ रही है। बल्कि जिस अनुपात में यह कर्ज लिया जा रहा है उसके मद्देनजर यह सवाल उठाना शुरू हो गया है कि आखिर इस कर्ज का निवेश हो कहां रहा है। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह चिन्ता व्यक्त की है की कर्ज का 70% सरकार के वेतन पैन्शन और ब्याज के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इस परिदृश्य में यह स्वभाविक है कि जिस अनुपात में कर्ज बढ़ेगा उसी अनुपात में नियमित और स्थायी रोजगार में कमी आती चली जायेगी।

यह सरकार विधानसभा चुनाव में दस गारंटियां बांट कर सत्ता में आयी थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में यहां का सरकारी कर्मचारी, बेरोजगार युवा और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन योजना की बहाली की गारंटी दी। बेरोजगार युवाओं को पांच वर्ष में पांच लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था जिसके मुताबिक हर वर्ष एक लाख नौकरी दी जानी थी। 18 वर्ष से 59 वर्ष की हर महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का वायदा किया गया और इसके तहत प्रदेश भर से 18 लाख महिलाओं को यह लाभ दिया जाना था। परन्तु आज प्रति वर्ष एक लाख नौकरियां देने के स्थान पर इस संबंध में पूछे गये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हर सवाल के जवाब में सदन में यही कहा गया की सूचना एकत्रित की जा रही है। कर्मचारियों को ओ.पी.एस. देने के मामले में निगमों-बोर्डो के कर्मचारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं और हर दिन इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार ओ.पी.एस. की जगह अब यू.पी.एस. की बात करने लग पड़ी है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी यह सरकार नहीं कर पायी है 11% का एरियर खड़ा हो गया है। संशोधित वेतनमानों का भुगतान नहीं हो पाया है। महिलाओं को 1500 प्रतिमाह दिये जाने का आंकड़ा 35687 महिलाओं पर ही आकर रुक गया है। जबकि वायदा 18 लाख महिलाओं से किया गया था। जब यह सवाल पूछा गया कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को विभिन्न महिला योजनाओं के तहत कितना लाभ मिल रहा है तो जवाब में कहा गया की सूचना एकत्रित की जा रही है।

सरकार से नियुक्त सलाहकारों को लेकर प्रश्न पूछा गया तो जवाब दिया गया की सूचना एकत्रित की जा रही है। निगमों/बोर्डो में नियुक्त अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को लेकर पूछे गये प्रश्न का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। रोजगार को लेकर पूछे गये प्रश्नों का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। सदन में तो इस तरह के जवाब से तो थोड़ी देर के लिये

शेष पृष्ठ 8 पर.....

# क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के पद पर प्रवीण गुप्ता की नियुक्ति एक सफल प्रयोग होगा?

**शिमला/शैल।** इस बार बरसात में जिस स्तर पर प्रदेश में जानमाल का नुकसान हुआ है उसका संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस पैमाने पर लिया है उसके दुरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सारे संबद्ध विभागों से इस बारे में जवाब तलब किया है। प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और फोरलेन निर्माणों की अनिवार्यता पर बहस चल पड़ी है कि क्या इन निर्माणों की प्रदेश को आवश्यकता है भी या नहीं। केन्द्र सरकार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इस नुकसान के लिये इनकी डी.पी.आर. की गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया है। इस परिदृश्य में राज्यों के वह सारे विभाग चर्चा में आ गये हैं जो पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन के लिये जिम्मेदार माने जाते हैं। क्या इन विभागों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभायी है? इन विभागों ने इस नुकसान के लिये किन कारकों को जिम्मेदार ठहराया है और सर्वोच्च न्यायालय में क्या जवाब दिया है यह तो अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है लेकिन यह तय है कि आने वाले समय में इन संबद्ध विभागों पर आम आदमी की बराबर नजर रहेगी।

इस वस्तु स्थिति में हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गुप्ता मुख्य अभियन्ता पर्यावरण को अगले आदेशों तक यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति को वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है क्योंकि पर्यावरण प्रभावों का आकलन एक पर्यावरण अभियन्ता ही जिस स्टीकता से रेखांकित कर सकता है वैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी शायद नहीं कर सकता है। वर्तमान परिदृश्य में सरकार के इस प्रयोग पर आम आदमी की नजरें लग गयी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रवीण गुप्ता क्या सरकार के दबाव को नजरअन्दाज करके प्रदेश हित में फैसला ले पायेंगे।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

# शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया

**शिमला/शैल।** शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 19 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश के एक शिक्षक को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इस वर्ष पहली बार महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के 19 शिक्षकों को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र के साथ पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे कठिन भौगोलिक राज्य में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक अतुलनीय योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक का सर्वप्रथम स्थान है। अपने शिक्षकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गुरू अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान के प्रकाश से रौशन करता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षित समाज का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत भारत की नींव रखते हैं।

शुक्ला ने शिक्षकों से कक्षाओं की परिधि से बाहर निकलकर नवाचार को अपनाने और विद्यार्थियों का विकास संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में करने का आहवान किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपराओं, मूल्यों, अनुसंधान और नवाचार में निहित समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व पर बल दिया। परख 2025 सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान




हासिल करने की हिमाचल प्रदेश की उपलब्धि की सराहना करते हुए, उन्होंने पूरे शिक्षण समुदाय को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

राज्यपाल ने नशामुक्त हिमाचल अभियान में शिक्षकों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया। प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति के दृष्टिगत राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास की अंधी दौड़, अनियोजित निर्माण कार्यों और वनों के कटान से पर्यावरण की क्षति हो रही है। उन्होंने कहा, नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश में दुनियाभर से पर्यटक आते हैं, इसलिए प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने पुरस्कारों के लिए पारदर्शी चयन, शिक्षकों के लिए विदेश के शैक्षणिक भ्रमण, छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण और राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग जैसी अभिनव पहलों पर प्रकाश डाला।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई दी और पहली बार पुरस्कारों में तकनीकी शिक्षा शिक्षकों को शामिल करने के लिए आभार व्यक्त किया।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, निदेशक, उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजेश शर्मा और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# प्राथमिकता के आधार पर 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे स्थापित : उप-मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य में हरित परिवहन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 327 इलेक्ट्रिक बसों (297 टाइप-1 और 30 टाइप-3 के सुचारू संचालन के लिए 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन तथा अन्य अधोसंरचना के विकास के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 110.95 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्राप्त हुई है। योजना के अंतर्गत 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 46 स्थानों का चयन किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर 34 स्थानों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें शिमला लोकल वर्कशॉप, ठियोग बस स्टैंड, नूरपुर, फतेहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, हमीरपुर वर्कशॉप, हमीरपुर बस स्टैंड, नादौन बस स्टैंड, नया इलेक्ट्रिक डिपो नादौन, ऊना, बंगाणा, अंब, बिलासपुर, घुमारवीं, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, मंडी वर्कश प, अर्की, परवाणु, नालागढ़, नाहन, पांवटा साहिब, रेणुका जी, कुल्लू, मनाली, चंबा, भरमौर, डलहौजी, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, रिकांगपिओ और केलंग शामिल हैं।

अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ई-मोबिलिटी क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार और अधोसंरचना विकास के नए द्वार भी खोल रही है।

उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जबकि सिविल कार्यों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। यह कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा ताकि ई-बसों के पहले बेड़े के आने से पूर्व आवश्यक तैयारियां पूरी हो सकें।

# राज्य में स्कूल और कॉलेज 7 सितम्बर तक बंद रहेंगे: शिक्षा मंत्री

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च और स्कूल शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने, सड़कें अवरुद्ध होने और शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। लगभग 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिनका अनुमानित नुकसान लगभग 50 करोड़ रुपये है।

मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और डाइट 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी इस अवधि के दौरान संस्थानों में आने से छूट दी गई है। संस्थानों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि जहां तक संभव हो, कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं।

# लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अत्याधुनिक इंजिनियरिंग तकनीकों से लैस करने की आवश्यकता: डॉ. अभिषेक जैन

**शिमला/शैल।** लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर जारी किया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आधुनिक तकनीकों के अनुरूप कौशल उन्नयन, वित्तीय एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर सचिव ने कहा कि अब तय कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष उपमंडल स्तर के अधिकारियों से लेकर ऊपरी स्तर तक के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कैलेंडर न केवल सेवा के दौरान कौशल संवर्धन पर केंद्रित है, बल्कि भविष्य के लिए क्षमता निर्माण पर भी बल देगा।

उन्होंने कहा कि अधोसंरचना के विकास में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को आईआईटी, एनआईटी, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी नोयडा, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, हिपा और अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग व प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से विशेष तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल से अधिकारियों की दक्षता, सड़क सुरक्षा, सतत् आधारभूत ढांचा, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक, ई-गवर्नेंस, परियोजना प्रबंधन और नई निर्माण सामग्रियों के उपयोग जैसे विषयों की जानकारी प्राप्त होगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुमोदन के अनुरूप इस कैलेंडर में पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कनिष्ठ अभियंता से उपमंडल अधिकारी और अधिशासी अभियंता तक की पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अलावा, विभाग के सभी विद्युत, यांत्रिक और वास्तुशिल्प अधिकारियों के लिए जोनल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डॉ. जैन ने कहा कि तकनीकी प्रगति को देखते हुए सड़कों, सुरंगों, पुलों और भवनों के डिजाइन और निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग इनपुट की आवश्यकता बढ़ रही है। प्रशिक्षण में भू-तकनीकी अध्ययन, पर्यावरण आकलन, डिजिटल उपकरणों जैसे बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग बीआईएम, जीआईएस आधारित योजना और ड्रोन से सर्वेक्षण जैसी नई तकनीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बाह्य सहयोग के साथ-साथ विभाग द्वारा प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों की भागीदारी से इन-हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल भी शुरू किए जाएंगे। प्रथम चरण में लगभग 400 वरिष्ठ अधिकारियों को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य है, ताकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी और वित्तीय व्यवस्थाओं से निरंतर अपडेट किया जा सके।

डॉ जैन ने कहा कि यह व्यापक प्रशिक्षण पहल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता के कारण संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि यह नया प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग की दक्षता, जवाबदेही और सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाएगा और हिमाचल प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में इंट्रा-सर्किल रोमिंग सुविधा जारी रहेगी

**शिमला/शैल।** दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र एचपी एलएसए के अपर महानिदेशक दूरसंचार ने सूचित किया है कि चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ज़िलों में इंट्रा-सर्किल रोमिंग आईसीआर सुविधा को 7 दिन और बढ़ाते हुए यानी 10 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है।

प्रभावित क्षेत्र में निरंतर मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। क्षेत्र के मोबाइल उपयोगकर्ता अपने डिवाइस सेटिंग्स से किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का चयन कर सकते हैं, चाहे उनका मूल सेवा प्रदाता कोई भी हो। आईसीआर सक्रियण अवधि के दौरान, उपयोगकर्ता क्षेत्र में कवरेज वाले किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

इस अस्थायी व्यवस्था का उद्देश्य भारी बारिश के कारण जारी व्यवधान के दौरान निर्बाध मोबाइल संचार सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# नरदेव सिंह कंवर ने अधिकारियों से उपकर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कहा

**शिमला/शैल।** राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों से उपकर संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह बात बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बोर्ड



की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिगत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कामगारों के कल्याण के लिए योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी प्रतिष्ठानों से उपकर संग्रह बहुत कम है। उन्होंने उपकर संग्रह पर विशेष बल देते हुए कहा कि उपकर से एकत्रित धनराशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल विकास भत्ते, बच्चों की शिक्षा और दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से इस वित्तीय वर्ष के दौरान उपकर संग्रह को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने के निर्देश दिए।

उन्होंने श्रम अधिकारियों को निजी बिल्डरों, पेट्रोल पंपों, होटलों, कारखानों, निजी शिक्षण संस्थानों, शॉपिंग मॉल आदि सहित विभिन्न संस्थाओं से उपकर की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्माण एवं अन्य श्रमिकों का उचित सत्यापन सुनिश्चित कर उनका पंजीकरण करने पर बल दिया।

बैठक में सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड राजीव कुमार, श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा, उप श्रम आयुक्त मुनीष करोल और सभी जिलों के श्रम अधिकारी उपस्थित थे।

# आपदा प्रभावितों को वन भूमि और विशेष राहत पैकेज के लिए केन्द्र पर दबाव बनाएं भाजपा सांसद:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का

आकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और स्थानीय निवासियों की निजी सम्पतियों को हुई क्षति का पूर्ण जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बात की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। मनाली के वशिष्ठ चौक पर मुख्यमंत्री ने बीआरओ अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया और मृतकों के परिवारों के साथ संवदेना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यो में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त भुंतर पुल तथा भूतनाथ पुल का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष मॉनसून के दौरान प्रदेशभर में भारी तबाही हुई है, जिससे जान-माल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए प्रशासन ने सेना के चिनूक तथा एम आई-17 हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली हैं तथा श्रद्धालुओं को भरमौर से चम्बा निकालकर उन्हें उनके गंतव्य की ओर बिना किसी शुल्क के एचआरटीसी की बसों से रवाना किया गया। उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों एवं बागवानों के उत्पादों को भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों से निकलकर मण्डियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार की प्राथमिकता सड़कों को बहाल करना तथा बिजली व पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और सामान खराब हो गया है, उन्हें राज्य सरकार 7.70 लाख रूपये की सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा पशु धन की हानि के लिए भी उचित मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता अपने सीमित संसाधनों से कर रही है और अभी तक केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए एक बीघा जमीन वन भूमि में प्रदान करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 प्रतिशत जमीन वन भूमि है तथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना आपदा प्रभावितों को यह जमीन नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा तथा उनके सांसदों को प्रभावित परिवारों को एक बीघा वन भूमि तथा विशेष राहत पैकेज के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा नेता केवल सोशल मीडिया में सक्रिय है, उन्होंने जमीनी स्तर पर आपदा प्रभावित लोगों के लिए कुछ नहीं किया है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के दृष्टिगत विश्व बैंक से 3000 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना भी बनाई है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने मण्डी और कुल्लू जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

# 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र लगेंगी नई सीटी स्कैन मशीनें:स्वास्थ्य मंत्री

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि

प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र ही अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया तीन महीनों में पूरी कर दी जाएगी तथा दिसम्बर, 2025 तक प्रदेश की जनता इन सेवाओं का लाभ उठा सकेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन मशीनों के स्थापित होने से लोगों को निकटवर्ती स्थानों पर ही आधुनिक और विश्वसनीय सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मशीनें सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, राजगढ़, अर्की, नालागढ़, नादौन, देहरा, जवाली, अंब, चौपाल, रोहडू, ठियोग, रिकांगपिओ, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, घुमारवीं, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, मनाली, आनी, भरमौर, चौहड़ी और भोरंज में स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जोनल अस्पताल धर्मशाला और डीडीयू शिमला तथा क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सोलन, केलांग और कुल्लू सहित एमजीएमएससी खनेरी रामपुर तथा अन्य स्थानों में भी यह मशीनें स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय राशि सहित हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों की सूची, उनके समयबद्ध निर्माण हेतु आवश्यक बजट तथा स्टाफ की आवश्यकता का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही अनुमान तैयार होंगे, सरकार उनके निर्माण और अत्याधुनिक मशीनों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करेगी। साथ ही स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी तुरंत आरंभ कर दी जाएगी।

डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि सर्जरी के लिए पांच फेको मशीनें भी खरीदी गई हैं, जिन्हें चंबा चिकित्सा महाविद्यायल, क्षेत्रीय अस्पताल चंबा और सिविल अस्पताल रोहडू, पांवटा साहिब और ऊना में स्थापित किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश में स्थापना प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में दवाओं और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की खरीद त्रैमासिक आधार पर की जाती है जिससे बार-बार औपचारिकताओं और अनुमोदन में विलंब होता है। इस समस्या से निपटने से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे निर्बाध और शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान की त्रैमासिक खरीद व्यवस्था को बदलकर अर्धवार्षिक आधार पर करने की प्रणाली स्थापित करना विचाराधीन है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिशु देखभाल किट्स में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। सरकारी या निजी अस्पतालों में जन्मे नवजात शिशुओं को कुल 18 वस्तुएं इन किट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन किट्स में प्रदान की जाने वाली 18 वस्तुओं के नमूने सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के बाद इनके ऑर्डर दिए जाएंगे।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपिल, एचपीएमएससीएल के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंगल, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन जितेंद्र सांजटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# मणिमहेश यात्रियों के लिए एचआरटीसी की नि:शुल्क बस सेवा रहेगी जारी:मुकेश अग्निहोत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी मणिमहेश याा से लौट रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए लगातार नि:शुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 153 बसों के माध्यम से लगभग 6,647 श्रद्धालुओं को नि:शुल्क पठानकोट और कांगड़ा तक पहुंचाया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में श्रद्धालुओं की सुरक्षित घर वापसी सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम का दायित्व है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

# भरमौर से 1166 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले गए

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की निगरानी में चलाए गए बड़े बचाव अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान भरमौर क्षेत्र से फंसे

हुए 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया गया। सभी श्रद्धालुओं को एचआरटीसी बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक नि:शुल्क भेजा गया।

आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की 12 उड़ानों के जरिए 524 यात्रियों को भरमौर से एयरलिफ्ट किया गया। तीन शवों को भी भरमौर से चंबा लाया गया। पिछले कल भी 7 उड़ानों के माध्यम से 35 यात्रियों को भरमौर से नि:शुल्क एयरलिफ्ट किया गया था।

इसी दौरान चंबा जिला प्रशासन ने 607 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा तक सड़क मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया। क्षतिग्रस्त सड़कों पर यात्रियों को पैदल चलना पड़ा, वहां उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए। रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। चंबा पहुंचने के बाद इन श्रद्धालुओं को देर रात एचआरटीसी की 13 बसों के माध्यम से नूरपुर और पठानकोट भेजा गया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस बचाव अभियान की लगातार निगरानी करते रहे और निरंतर जानकारी लेते रहे। वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी स्वयं भरमौर में निरंतर पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

कुल्लू में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल, होमगार्ड, जिला प्रशासन चंबा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, एनजीओ और स्वयंसेवियों के राहत व बचाव कार्य में किए गए अथक प्रयासों की सराहना की है।

# राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा नियमों में ढील दी

**शिमला/शैल।** प्रदेश में मानसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप, इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना की मरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश, अचानक बाढ़ और बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है। कृषि व बागवानी क्षेत्र, पशुधन और ग्रामीण अधोसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। खराब मौसम की स्थिति में ऐसी बैठकें आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उपायुक्त अब भूमि विकास परियोजनाओं सहित सभी श्रेणियों के कार्यो को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए प्रति ग्राम पंचायत 20 कार्यो की पूर्व सीमा में भी ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त, भूमि विकास परियोजनाओं के व्यक्तिगत कार्यो के लिए वित्तीय सीमा को प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल क्षतिग्रस्त ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी बल्कि इस चुनौतीपूर्ण समय में ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

अहिंसा मेरे विश्वास का पहला अनुच्छेद है। यह मेरे पंथ का अंतिम अनुच्छेद भी है।

.....महात्मा गांधी

## सम्पादकीय

# वोट चोरी के आरोपों से राजनीतिक संकट बढ़ा

राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिस प्रामाणिकता के साथ खुलासा देश की जनता के सामने रखा है उससे पूरे देश में चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। क्योंकि इन आरोपों पर चुनाव आयोग अपना प्रमाणिक रिकॉर्ड जनता में जारी करके अपना स्पष्टीकरण देने की बजाये राहुल गांधी से ही शपथ पत्र की मांग करके और भी प्रश्नित हो गया है। वोट चोरी का आरोप एक जन मुद्दा बन चुका है और आम आदमी को यह समझ आ गया है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल का ही पक्षधर बनकर रह गया है। वोट चोरी के आरोप पर जिस तरह का जन समर्थन राहुल गांधी को मिला है उससे स्पष्ट हो गया है की आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। क्योंकि इस जन मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिये जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां को मंच से गाली देने का खेल खेला गया और गाली देने वाला एक भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला उससे सत्ता पक्ष की हताशा ही जनता के सामने आयी है।

इस समय इस गाली वाले मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक क्षमा याचना की मांग की है उससे वह पुराने सारे दृश्य जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक भाजपा नेताओं द्वारा स्वयं सोनिया गांधी और शशिथरूर की पत्नी पर जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुये उन्हें संबोधित किया गया था एकदम नए सिरे से चर्चा में आ गये हैं। भाजपा के एक भी नेता द्वारा उन अपशब्दों पर एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया गया। बल्कि इसी दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर भाजपा नेता डॉ. स्वामी ने जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर लगाये हैं और पूरी भाजपा डॉ. स्वामी को लेकर एकदम मौन साधकर बैठ गयी है उससे स्थिति और भी गंभीर हो गयी है। इन्हीं आरोपों के दौरान प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो सवाल उठे हैं उन पर भी भाजपा नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आयी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को लेकर जिस तरह का विवाद अमेरिकी अदालत के माध्यम से सामने आया है उससे भी प्रधानमंत्री की छवि पर कई गंभीर प्रश्न चिन्ह स्वत: ही लग गये हैं। भाजपा का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री पर जिस तरह के सवाल खड़े हो गये हैं उनका परिणाम गंभीर होगा यह तय है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद त्याग पर उठी चर्चाओं ने भाजपा और मोदी के राजनीतिक चरित्र पर जिस तरह के सवाल खड़े किये हैं उससे स्थिति और भी सन्देहास्पद हो गयी है। भाजपा के इस राजनीतिक चरित्र पर भी सवाल उठने लग पड़े हैं कि भाजपा का साथ देने वाले दलों का राजनीतिक भविष्य कितना सुरक्षित रह पाता है। पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के इस चरित्र का प्रमाण है। कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाने से पूर्व इस संद्धर्भ में पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण जूटा कर चुनाव आयोग kkऔर इससे लाभान्वित होती रही भाजपा की राजनीति पर हमला बोला है उससे पूरे देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उसका जवाब चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से नहीं आ पा रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह के सवालों से घिर गये हैं उसके परिणाम भाजपा की राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह प्रमाणित होंगे। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार की एस.आई.आर. पर जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा है उससे सारा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया है। ऐसी स्थितियां बन गयी हैं जिनसे केंद्र की सरकार पर संकट आता नजर आ रहा है। इस राजनीतिक परिदृश्य में यदि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर बैठे भाजपा के स्लीपर सैलों को चिन्हित करके बाहर का रास्ता न दिखा पाये तो इससे राहुल को कांग्रेस के अन्दर भी एक बड़ी लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। क्योंकि देश की राजनीति इस समय जिस मोड़ पर पहुंच गयी है उसमें इस तरह के भीतरघात का सबसे अधिक डर रहता है। क्योंकि आसानी से कोई सत्ता नहीं छोड़ता है।

# अप्रत्यक्ष रूप से चीन को फायदा पहुंचा रहा है अमेरिका, टैरिफ वॉर से चाइना प्लस वन रणनीति को लगा धक्का

गौतम चौधरी

संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अभी हाल ही में भारत के खिलाफ लगाए गए 50 प्रतिशत तक सीमा शुल्क का सबसे बड़ा असर, चाइना प्लस वन रणनीति पर पड़ने वाला है। इससे सीधा लाभ चीन को पहुंचेगा। अमेरिकी हालिया रणनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे वह चीन के खिलाफ कितना भी दिखावा कर ले लेकिन अमेरिकी रणनीतिकार अप्रत्यक्ष रूप से चीन का लगातार सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करना स्वाभाविक भी है क्योंकि दुनिया के बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों की पूंजी चीन ने अपने यहां निवेश करवा रखा है। यदि चीन किसी कारण धरासायी होता है तो वहां निवेशित पूंजी को डूबने की पूरी संभावना है। इस बात से अमेरिका भी डरता है और जब कभी भी चीन कमजोर पड़ने लगता है अमेरिका किसी न किसी रूप से उसकी मदद कर देता है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर अमेरिका चीन की मदद क्यों करता रहा है?

दरअसल, जब औटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ग्रेट ब्रिटेन का विकास हुआ, तब दुनिया बदल चुकी थी और नए तरह की व्यवस्था खड़ी होने लगी थी। दुनिया भर के व्यापारी और पूंजीपरस्थ ग्रेट ब्रिटेन का संरक्षण प्राप्त करने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर दुनिया बदली और ग्रेट ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। अब दुनिया के पूंजीपरस्थों का संरक्षक कौन होगा? ऐसे में इन पूंजीपरस्थों के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में उभरकर सामने आए अमेरिका के तत्कालिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। हालांकि द्वितीय विश्वयुद्ध के थोड़े ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गयी लेकिन उन्होंने अपने सैन्य ताकत के बल पर दुनिया के पूंजीपरस्थों को संरक्षित करने का आस्वासन दिया। इधर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संगठित पूंजीपरस्थों के खिलाफ एक नया ब्लॉक बना। उस ब्लॉक का नेता नेता, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन कर उभरा। फिर नए वैश्विक रणनीति का उदय हुआ। पूंजीवाद और साम्यवाद की के बीच दुनिया विभाजित हो गयी। साम्यवादी प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ता गया वैसे-वैसे साम्रज्यवादी प्रभाव के कारण नए-नए देश आजाद होने लगे। साम्यवादी प्रभाव के कारण जो देश आजाद हो रहे थे वह साम्यवादी रूस के साथ होता जा रहा था। इस बात को लेकर दुनिया के पूंजीपरस्थ चिंतित होने लगे और इस बात की चिंता संयुक्त राज्य अमेरिका को भी होने लगी। इसी बीच चीन के किसानों ने वहां के राजा और सामंतों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया। साम्यवादी रूस ने उस आंदोलन को सहयोग करना प्रारंभ किया। इधर सत्ता पक्ष को अमेरिका ने सहयोग कर दिया। अंततोगत्वा वर्ष 1949 में चीन में भी माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। अब चीन का नाम भी बदल दिया गया। अब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा और उसका नाम पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। माओ और चीनी साम्यवादी नेता रूस के साथ मिल कर दुनिया में साम्यवाद का अलख जगाने की कसमें खा रहे थे लेकिन इधर चीन अपनी सीमा में विस्तार को लेकर भी संवेदनशील था। साम्यवादी रूस की सीमा साम्यवादी चीन से मिलने गली। चीन अपनी सीमा विस्तार की नीति पर आगे बढ़ने लगा। इससे रूस को आपत्ति हुई और दोनों में सीमा विवाद प्रारंभ हो गया। इसी मौके का फायदा पूंजीवादी अमेरिका ने उठाया और चीन को सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। साम्यवादी खाल में चीन कब पूंजीवादी हो गया पता ही नहीं चला। दुनिया भर की व्यक्तिगत या क रपोरेटी पूंजी की सुरक्षा करने वाला अमेरिका, साम्यवादी चीन का दोस्त बन गया। अब चीन में डेंग शियाओ पिंग का दौर प्रारंभ हो गया था। चीन पूरी तरह बदल गया। चीन रूस को छोड़ अमेरिका का साथ बन गया और बड़े पैमाने पर अमेरिकी संरक्षित पूंजीपरस्थों ने चीन में निवेश किया। आज का चीन उसी पूंजी से दुनिया पर पर बढ़ बनाते जा रहा है।

जब चीन अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों पर भारी पड़ने लगा तो पश्चिम के रणनीतिकारों ने चीन की मोनोपोली को कम करने के लिए भारत को खड़ा करने की कोशिश प्रारंभ की। उसी रणनीति का परिणाम चाइना प्लस वन पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत भारत के पास वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का अवसर प्राप्त होने लगा था। अब थोड़ा इस रणनीति को समझ लेना ठीक रहेगा। यह रणनीति कंपनियों की वैश्विक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है जिसमें कंपनियाँ चीन के अतिरिक्त अन्य देशों में अपने परिचालन इकाई स्थापित कर अपने विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं का विस्तार करते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता के कारण होने वाले जोखिमों को कम करना है। विगत कुछ दशकों से चीन वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का केंद्र बन गया है, जिससे इसे 'वर्ल्ड्स फैक्ट्री' की संज्ञा दी जाने लगी है। दुनिया के देशों को इस बात की चिंता है कि अगर चीन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वैश्विक खतरा पैदा हो सकता है। चाइना प्लस वन रणनीति इसी सोच का प्रतिफल है। इस रणनीति के कारण बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंध विनिर्माण कंपनी, फॉक्सकॉन ने भारत में धराधर अपनी शाखा खोलना प्रारंभ की। यही नहीं ऐसी कई कंपनियों ने भारत का रूख लिया था। जिसके कारण चीनी रणनीतिकार दबाव में दिखने लगे थे। अब ऐन वक्त अमेरिकी नेतृत्व ने भारत पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लाद कर अप्रत्यक्ष रूप से चीन का सहयोग कर दिया है।

वैसे अमेरिकी टैरिफ आक्रमण के कई अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण हैं लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि अमेरिका चीन के खिलाफ चाहे जितना बोल ले लेकिन वह चीन को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं देखना चाहता है। इसके कई कारण चीन-अमेरिकी संबंधों के इतिहास में छुपा है।

# शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: सावित्री बाई फुले की विरासत

शिक्षक दिवस उन महान व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का अवसर है, जो अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से राष्ट्र का भविष्य संवारते हैं। इस दिन हम भारत

**सावित्री ठाकुर**
**महिला एवं बाल विकास**
**राज्य मंत्री भारत सरकार**

की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले (1831–1897) को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश में महिला शिक्षा की नींव रखने के लिए पुराने सामाजिक पूर्वाग्रहों को साहसपूर्वक चुनौती दी थी।

ऐसे दौर में जब महिलाओं की शिक्षा को नापसंद किया जाता था और अक्सर हिंसक तरीके से इसका विरोध किया जाता था, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि पाठयक्रम भी तैयार किए और महिलाओं को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करने हेतु कविताएं भी लिखीं। उनका जीवन साहस का प्रमाण था–वह रोज़ाना एक अतिरिक्त साड़ी के साथ स्कूल जाती थीं, क्योंकि रूढ़िवादी पुरुष उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। फिर भी वह डटी रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि भारत का भविष्य उसकी बेटियों की शिक्षा में निहित है।

**सुधारकों की विरासत और समानता का आहवान**

सावित्रीबाई फुले अपने संघर्ष में अकेली नहीं थीं। भारत के समाज सुधार की यात्रा को राजा राम मोहन राय जैसे महान व्यक्तित्वों ने दिशा दी, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा की वकालत की। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि 'महिलाओं की शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शद्रिशाली माध्यम है।' इन सभी सुधारकों का मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षा से सशक्त नहीं होंगी, भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती।

यह विरासत आज भी आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की विकास यात्रा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से आगे बढ़ेगी। 'विकसित भारत@2047' का विज़न भी इसी सोच पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार बनाया गया है, और इस सशक्तिकरण की नींव शिक्षा है।

**महिलाएं और शिक्षा: अब तक की प्रगति**

स्वतंत्रता के बाद से इस दिशा में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। महिला साक्षरता, जो 1951 में मुश्किल से 8.86 प्रतिशत थी, आज बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो चुकी है और हाल के सर्वेक्षणों से स्कूलों में लड़कियों के बढ़ते नामांकन यह इंगित करते हैं कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) 2021–22 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अब लड़कों की तुलना में अधिक है।

मोदी सरकार ने 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की, जिसने समाज की सोच बदली, बाल लिंगानुपात में सुधार किया और स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाया। पोषण अभियान, मिशन शक्ति और सामर्थ्य जैसी पहल मिलकर ऐसा ढांचा तैयार करती हैं, जिसमें शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और अवसर का सहारा मिलता है। यूडीआईएसई+ 2024–25 के आंकड़े बताते हैं कि पहली बार भारत में महिला शिक्षकों की संख्या कुल स्कूली शिक्षकों का 54.2 प्रतिशत हो गई है, जो 2014–15 के 46.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया है। यह संस्थान महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। सावित्रीबाई फुले के नाम के साथ, यह संस्थान शिक्षा और सुधार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के उनके विजन के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि है।

फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कम उम्र में विवाह, सुरक्षा की चिंता और आर्थिक कारणों से कई लड़कियां माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देती हैं। सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा, मासिक धर्म स्वच्छता पहल और डिजिटल शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रही है, ताकि हर लड़की बिना रुकावट अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

**राष्ट्र–निर्माता के रूप में शिक्षक**

महिला शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल पढ़ाने का काम नहीं करतीं, बल्कि लाखों बालिकाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श भी बनती हैं। इसी तरह वे सावित्रीबाई फुले की मशाल को आगे बढ़ा रही हैं। अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति से लड़कियों का स्कूल में नामांकन और पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने और परिवारों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाने में उनका योगदान बेहद अहम है।

**विकसित भारत की ओर**

जैसे–जैसे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, शिक्षा विकास का प्रमुख वाहक बनी हुई है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है:

शिक्षित महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य सेवा, कम शिशु मृत्युदर, उच्च पारिवारिक आय और मज़बूत समुदाय सुनिश्चित करती हैं। यूनेस्को के अनुसार, एक लड़की की स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष उसकी भविष्य की आय में 10–20 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

इसलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं को सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्णशिक्षा) और सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) के अनुरूप बनाना जारी रखे हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लड़की पीछे न छूटे। हम शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़कर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहां महिलाएं विद्यार्थी, शिक्षक, उद्यमी और नेता बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

**सामूहिक संकल्प**

सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति साहस से ही जन्म लेती है। पुणे की उनकी साधारण कक्षा से लेकर आधुनिक भारत की उन कक्षाओं तक, जहां करोड़ें लड़कियां प्रतिदिन शिक्षाग्रहण करती हैं, यह यात्रा महिलाओं और शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आये व्यापक बदलाव को दर्शाती है। लेकिन यह मिशन अभी अधूरा है।

शिक्षक दिवस को मनाते हुए, आइए हम उनके विजन और हमारे प्रधानमंत्री के इस आहवान के प्रति स्वयं को पुनःसमर्पित करें कि महिला सशक्तिकरण कल्याण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का विषय है। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक लड़की शिक्षित हो, प्रत्येक महिला सशक्त हो और प्रत्येक शिक्षक का सम्मान हो, हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं।

सावित्रीबाई फुले की विरासत केवल इतिहास नहीं है–यह हमारे वर्तमान के लिए जीवंत मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रकाशस्तंभ है। उनके साहस के प्रकाश में हम यह देख सकते हैं कि विकसित भारत का मार्ग उसके बेटियों और बेटों द्वारा समान रूप से नेतृत्व किया जाएगा।

# हिमालयी आपदाएं: चुनौतियां और समाधान

राजन कुमार शर्मा

**शिमला।** पश्चिम हिमालय, जो अपनी सुरम्य वादियों, सदाबहार हिमालयी श्रृंखलाओं और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा और ग्लेशियर पिघलने की घटनाओं में तीव्रता देखी जा रही है। इन घटनाओं के लिए कई बार पर्यावरणीय क्षति, मानवीय लापरवाही या विकास परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या यह सब दोषारोपण उचित है? क्या हमें इस संकट की तह तक जाकर मौसम और प्रा तिक प्रक्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता नहीं? हिमालय और मौसमी अस्थिरता हिमालय, दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला, लगातार भूवैज्ञानिक और मौसमीय बदलावों के अधीन है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्षेत्रिय तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हिमनदों का पिघलना तेज हो गया है। इसके साथ ही, म नसून के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति अप्रत्याशित हो रही है। ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही हैं और आपदाओं की संभावना को बढ़ा रही हैं। विकास और पर्यावरणीय संतुलन विकास की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास सतत नहीं हो सकता। पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध सड़क निर्माण, कटान और जंगलों की कटाई ने मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया है। लेकिन साथ ही, मौसमी बदलाव और प्राकृतिक चक्रों का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत: दोषारोपण के बजाय हमें दोनों पहलुओं को समझ कर संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। समाधान की ओर कदम स्थानीय समुदायों की भागीदारी पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों की पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी हिमालय की ग्लेशियर गतिविधियों, वर्षा पैटर्न और भू–वैज्ञानिक परिवर्तनों पर लगातार अध्ययन और डेटा संग्रह आवश्यक है। विकास तो सभी चाहते हैं, विनाश नहीं। किसी भी निर्माण से पहले, पर्यावरण का पूरा आकलन होना चाहिए। मलबा कहाँ डालना है, कितने बाँध बनाने हैं, कितने चार–लेन राजमार्ग बनाने हैं। यह सब सोच–समझकर योजनाबद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मानो अंधी दौड़ चल रही है।क्या किया जाना चाहिए? वास्तव में, सभी नदियों, नालों, नालों और तालाबों का पूरा जोखिम आकलन किया जाना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्र इसमें मदद कर सकते हैं। निर्माण कार्य ऐसे आकलनों पर आधारित होना चाहिए और नदी या नाले की ज़मीन पर निर्माण प्रतिबंधित होना चाहिए। यह जोखिम आकलन जानकारी पटवारी स्थानीय राजस्व अधिकारी स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सोचना बचकाना है कि हम दीवार बनाकर नदी को रोक सकते हैं। भारी बारिश के दिन, नदी दीवार की ओर नहीं देखती। पहाड़ी नदियाँ अपने साथ पत्थर और शिलाखंड बहाकर ले जाती हैं। धराली नदी को ही देख लीजिए । यह विशाल शिलाखंडों को ढोती हुई खड़ी ढलानों से नीचे उतरती है( कोई भी दीवार इसका सामना कैसे कर सकती है? जलवायु परिवर्तन एक ढाल बन गया है. जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, वर्षा अनियमित हो रही है कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा और इससे अचानक बाढ़ आ रही है। पहाड़ों में बाढ़ सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि अचानक बाढ़ होती है। यह पहाड़ों की एक प्राकृतिक विशेषता है। बाढ़ ज़रूरी भी है, क्योंकि यह नदी को साफ़ करती है और मिट्टी और तलछट को बहा ले जाती है जो मैदानों को उपजाऊ बनाती है। लेकिन हकीकत में, जलवायु परिवर्तन सरकारों के लिए एक ढाल बन गया है। यह असली कारणों से ध्यान भटकाता है। सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि असली वजह यह है कि भूमि उपयोग और भूमि आवरण में भारी बदलाव आया है। 2030 तक हमें 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, लेकिन सतत विकास कैसे होगा? तभी जब योजना सही हो, जब भूमि उपयोग का उचित प्रबंधन हो। ज़रूरत मौसम को कोसने की नहीं, बल्कि उसके प्रति सचेत रहने की है। मौसम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने काम की योजना बनाएँ। नदी–नालों वाली ज़मीन से दूर रहें तभी बारिश तबाही में नहीं बदलेगी। साथ ही, यह भी याद रखना होगा कि जब तक व्यवस्था में सुशासन का अभाव रहेगा, पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती और सतत विकास संभव नहीं होगा। सतत विकास की नीतिरू विकास कार्यो में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और प्र ति के अनुकूल तकनीकों का उपयोग जरूरी है। आपदा प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्यो के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। निष्कर्ष हिमाचल प्रदेश की सुंदरता और जीवन शैली उसके प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर है। मौजूदा संकट के लिए सिर्फ एक कारक को दोष देना उचित नहीं होगा। हमें प्र ति के संकेतों को समझते हुए, मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। तभी हम हिमालय की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

# हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा:उप-मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये बड़े स्तर पर रोप-वे परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने बताया कि शिमला में 13.79 किलोमीटर लम्बी रोप-वे परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही इस परियोजना को आगामी चार वर्षों के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 3 लाइनें, 14 सेक्शन और 13 स्टेशन होंगे। सचिवालय, अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला में 50 करोड़ रुपये की लागत से 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 25 करोड़ रुपये की लागत से 3 प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरे किए जाएंगे।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत तीन महत्वाकांक्षी रोप-वे परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं। प्रदेश में 65 करोड रुपये की लागत से बाबा बालकनाथ मंदिर रोप-वे, 278.62 करोड़ रुपये की लागत से बिजली महादेव रोपवे और 76.50 करोड़ रुपये की लागत से माता चिंतपूर्णी मंदिर रोपवे परियोजना निर्मित की जा रही हैं। ये सभी परियोजनाएं जून, 2027 तक पूरी की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण कनेक्टिविटी की पहल को साकार करते हुए देश का पहला रोप-वे (बगलामुखी रोप-वे) दिसंबर, 2024 में शुरू किया गया। 53.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस रोप-वे से अब तक लगभग 69 हजार यात्री लाभ उठा चुके हैं। आपदा के समय यह रोप-वे स्थानीय लोगों और राहत कार्यों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ।

पर्यटन कनेक्टिविटी की दिशा में लंबी छलांग लगाते हुए कुल्लू के ढालपुर से पीज रोप-वे का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। 1.20 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 80 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे और इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए शिमला को परवाणु से रोप-वे परियोजना के तहत जोड़ने की योजना बनाई है। इस 38 कि.मी लम्बी परियोजना की अनुमानित लागत 5602.56 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट मोड पर पूरा करने की योजना है। पूरे देशभर में रोप-वे परियोजना को वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट की तर्ज़ पर लाने में यह परियोजना मील पत्थर साबित होगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में बनने वाली ये रोप-वे परियोजनाएं यातायात जाम की समस्या को दूर करेंगी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाएंगी और आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल परिवहन का विकल्प प्रदान करेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।

# मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों को दी शुभकामनाएं

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं विद्यार्थियों के शिक्षण में विशेष रुचि लेने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों को बधाई दी।

सोलन जिले के जेबीटी शिक्षक शशि पाल को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 19 शिक्षकों को शिमला में राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पांचवां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है, जो 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है।

# समय रहते उठाए गए सुरक्षात्मक उपायों से लारजी विद्युत परियोजना को नहीं पहुंचा नुकसान

**शिमला/शैल।** वर्ष 2023 की आपदा के अनुभव से हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष भारी बारिश और बाढ़ की चुनौती के बीच लारजी जलविद्युत परियोजना को सुरक्षित रखने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की तैयारियों के चलते 126 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहा तथा पावर हाउस पूरी तरह सुरक्षित रहा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोर्ड ने भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए एक व्यापक सुरक्षा योजना पर कार्य करना शुरू किया। समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाए, जिनमें फ्लड गेट्स की स्थापना प्रमुख रही। गेट्स के कारण ब्यास नदी में आई बाढ़ के बावजूद परियोजना स्थल और मुख्य प्रवेश द्वार सुरक्षित रहे तथा विद्युत गृह में रिसने वाले पानी को तुरंत निकाला गया। परिणामस्वरूप विद्युत गृह को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड प्रबंधन ने फरवरी 2025 में ही जनरेशन विंग के युक्तिकरण के तहत लारजी परियोजना में फील्ड और तकनीकी श्रेणियों के पद सृजित किए थे, जिससे परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सका। लारजी परियोजना की टीम ने स्थल पर सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए 26 अगस्त, 2025 को आई बाढ़ से गाद जमने की स्थिति में भी परियोजना को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की।

वर्ष 2023 में हुई तबाही के कारण लारजी जल विद्युत परियोजना लगभग छह महीने पूरी तरह से बंद रही थी, जिसके कारण लगभग 95 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना को फिर से सुचारु बनाने के लिए 185 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े थे। अगर सजगता के साथ सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए जाते तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को इतना ही नुकसान उठाना पड़ सकता था, जिससे राज्य सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता।

मुख्यमंत्री ने लारजी परियोजना को बाढ़ से बचाने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों पर संतोष व्यक्त किया और परियोजना विशेष सुरक्षा योजना को निरंतर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लारजी परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देने वाले बोर्ड प्रबंधन, अभियंताओं और कर्मचारियों की पूरी टीम को बधाई दी।

# नेशनल रैंकिंग में 3 श्रेणियों में नौणी विश्वविद्यालय को मिला स्थान

**शिमला/शैल।** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) 2025 की रैंकिंग जारी कर दी हैं। इन परिणामों की घोषणा कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई। इस वर्ष रैंकिंग को 17 श्रेणियों में जारी किया गया, जिनमें से तीन श्रेणियों में डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को स्थान मिला है।

देशभर में कृषि, वानिकी और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में नौणी 12वां स्थान पर रहा। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के श्रेणी में देशभर के सभी आईसीएआर संस्थाओं को गिनकर, विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान हासिल किया है।

विश्वविद्यालय ने निरंतर प्रगति दर्शाते हुए अपने अंकों में सुधार किया है। 2024 में 54.67 अंक से बढ़कर 2025 में 55.53 अंक प्राप्त किए हैं। 17 मानकों में से विश्वविद्यालय ने 9 मानकों में सुधार किया है तथा चार मानकों में पूर्ण अंक बनाए रखे हैं। यह सुधार मुख्यत: छात्र संख्या, प्राध्यापकों की योग्यता और अनुभव, शोध प्रकाशन, प्रकाशनों की गुणवत्ता, क्षेत्रीय विविधता और धारणा जैसे मानकों में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ है।

विषय-विशेष रैंकिंग के अलावा, नौणी को देशभर के विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 101-150 बैंड तथा ओवरऑल श्रेणी में 151-200 बैंड में भी स्थान मिला है।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय इन रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, जो बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के प्रति इसकी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कई मानकों में हमारे कुल अंकों में सुधार हुआ है, जो विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को दर्शाता है। हालांकि, हम उन मानकों का भी विश्लेषण कर रहे हैं जहाँ हमारा प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, ताकि सुधारात्मक कदम उठाकर आने वाले वर्षों में और बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

# चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति की 65 प्रतिशत क्षतिग्रस्त साइटें की गई क्रियाशील

**शिमला/शैल।** आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार गम्भीर प्रयास कर रही है, ताकि लोग अपने परिजनों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। 25 और 26 अगस्त, 2025 को हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में दूरसंचार नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 सितंबर, 2025 तक इन जिलों की 65 प्रतिशत क्षतिग्रस्त साइटों को क्रियाशील बनाना सुनिश्चित किया।

नेटवर्क आउटेज रिपोर्ट के अनुसार भीषण प्रा तिक आपदा के कारण चंबा जिले में एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया द्वारा संचालित कुल 1761 साइटों में से 27 अगस्त, 2025 तक 1155 लगभग 66 प्रतिशत साइटें निष्क्रिय थीं, जिससे संचार सुविधाएं बड़े पैमाने पर बाधित हुई।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल ने बताया कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 2 सितंबर, 2025 तक केवल 374 साइटें ही निष्क्रिय थीं। वर्तमान में चंबा जिला में नेटवर्क में 45 प्रतिशत सुधार हुआ है।

उन्होंने बताया कि भरमौर क्षेत्र में बीएसएनएल की दस साइटों में से पांच पर माइक्रो-वेव कनेक्टिविटी के माध्यम से नेटवर्क बहाल कर दिया गया है और शेष साइटों पर भी शीघ्र ही नेटवर्क बहाल कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सप्ताह के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी बहाल होने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि भरमौर क्षेत्र में रिलायंस जियो की कनेक्टिविटी 6 सितंबर तक चालू होने की संभावना है जबकि एयरटेल की 2जी सेवाएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं।

बुटेल ने बताया कि कुल्लू जिला में 2 सितंबर, 2025 तक एयरटेल दूरसंचार सेवाओं की 877 साइटों में से 84.9 प्रतिशत क्रियाशील कर दी गई, जबकि रिलायंस जियो की 1173 साइटों में से 65 प्रतिशत दूरसंचार सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। बीएसएनएल की 391 साइटों में से लगभग 20 प्रतिशत दूरसंचार सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। लाहौल-स्पीति ज़िला में एयरटेल की 63 साइटों में से 96.8 प्रतिशत दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, जबकि रिलायंस जियो सर्विसेज़ की 170 साइटों में से 84.1 प्रतिशत सेवाओं ने 2 सितंबर, 2025 तक सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया था।

# भाजपा ने चुनावी वर्ष में चहेतों को बांटे कामगार बोर्ड के 172 करोड़

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की शिमला में हुई समीक्षा बैठक में भाजपा शासनकाल में चुनावी वर्ष के दौरान चहेतों को लगभग 172 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटने का मुद्दा जोर-शोर से उठा। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने अधिकारियों से पूरे मामले में जवाबतलब किया है। जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को यह रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2021-22 में 72260 कामगारों का पंजीकरण रातों-रात किस आधार पर किसके दबाव में किया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद उस समय के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में कड़ी कारवाई की जाएगी।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि वर्ष 2021-22 की कामगारों की अब तक 204 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित हैं। पात्र कामगार, बोर्ड की योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए और रातों-रात पंजीकृत हुए कामगारों को रेवड़ियां बांट दी गई। बोर्ड ने चुनावी वर्ष में लाभान्वित हुए कामगारों की पात्रता संबंधी जांच बिठा दी है, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार में कामगारों के पंजीकरण व राशि वितरण में खूब फर्जीवाड़ा हुआ है। इससे उस समय के विभागीय मंत्री की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठ रही है। क्योंकि, अब तक की जांच में फर्जी पंजीकरण के 38 मामले पकड़े जा चुके हैं। इन मामलों में फर्जी लाभार्थियों पर हमीरपुर, भोरंज, बड़सर व सुजानपुर थाना में एफआईआर भी दर्ज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सजा के डर से 9 फर्जी लाभार्थियों ने 6 लाख रुपये की राशि बोर्ड को लौटा दी है। क्योंकि, बोर्ड के अधिनियम के अनुसार फर्जी तरीके से लाभ लेने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

**20 माह में 72,711 लाभार्थी कर दिए लाभान्वित**

अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 40696 लाभार्थी व 2022-23 में आठ महीने में 32015 लाभार्थी लाभान्वित किए गए। भाजपा ने बोर्ड को दोबारा चुनाव जीतने के लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले तक चहेतों को जमकर लाभ पहुंचाया।

**इन-इन मदों में बांटी राशि**

कंवर ने बताया कि पहली अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 92.33 करोड़ रुपये कामगारों को बांटे। जिनमें शादी के लिए 32 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 44 करोड़, चिकित्सा के लिए 1.30 करोड़ रुपये, मृत्यु पर 8.65 करोड़ रुपये, मातृत्व पर 5.24 करोड़ रुपये दिए गए। एक अप्रैल, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक आचार संहिता लगने से पहले 79.29 करोड़ रुपये बांटे गए। शिक्षा के लिए 52.21 करोड़ रुपये, मेडिकल के 19 लाख रुपये, मृत्यु पर 4.33 करोड़ रुपये, मातृत्व पर 2.39 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

**अब हिम परिवार पोर्टल के जरिये पंजीकरण**

कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए हिम परिवार पोर्टल को अनिवार्य किया है। अब तक के कार्यकाल में 14913 नए कामगार नियमों के तहत पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें 66 करोड़ रुपये की राशि सहायता के तौर पर प्रदान की गई है।

# प्रदेश ने हासिल की 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर, विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात में देशभर में अग्रणी

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में अपना नाम अंकित करवाने की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित 'पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह एवं उल्लास मेला–2025' के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित किया। यह कार्यक्रम निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'पूर्ण साक्षर राज्य' बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य इस उपलब्धि को निर्धारित समय सीमा से पूर्व हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि निरक्षर से पूर्ण साक्षर का सफर चुनौतियों भरा रहा है। हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ–साथ शिक्षा की सार्थकता बनाए रखने के लिए आधुनिक दौर के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक होता है। हिमाचल को यदि पूर्ण साक्षर राज्य के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर अग्रणी बनाए रखना है तो इस क्षेत्र में निरंतर सुधार करने होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किये गये सुधारों के फलस्वरूप हिमाचल में साक्षरता 99.30 प्रतिशत पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में कमी को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए। वर्तमान में विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात में प्रदेश देश भर में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव लाये जाएंगे। हम राज्य में विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं।

मुख्यमंत्री ने पूर्ण साक्षर राज्य के दृष्टिगत योगदान देने वाले अधिकारियों, स्वंयसेवकों और नव साक्षरों को सम्मानित किया। उन्होंने उल्लास कार्यक्रम के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। देश द्वारा आजादी प्राप्त करने के बाद हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में लगभग अंतिम पायदान पर था। प्रदेश की सभी सरकारों ने अपने–अपने कार्यकाल में ज्ञान की अलख जगाए रखी। प्रदेश में शिक्षा का सफ़र लगभग 7 प्रतिशत साक्षरता की दर से आरम्भ हुआ था। हमें गर्व है कि आज हिमाचल सम्पूर्ण भारत में पूर्ण साक्षर राज्यों की श्रेणी में अपना मकाम बनाने में सफल रहा है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति से अनेक कठिन निर्णय लिये हैं। प्रदेश में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर अब लगभग शून्य तक पहुंच चुकी है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा की गई नवीन पहलों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पूर्ण साक्षर राज्य का लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देने वाले व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया और बधाई दी।

केन्द्रीय सचिव शिक्षा संजय कुमार ने वीडियो संदेश द्वारा हिमाचल को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने नव साक्षरों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए हिमाचल ने विभिन्न मापदंडों के तहत उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी ताकि भविष्य की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया जा सके।

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने कहा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत 'जन–जन साक्षर' के ध्येय से कार्य करते हुए प्रदेश में अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

इस अवसर पर स्वंयसेवी अध्यापकों और नव साक्षरों ने अपने अनुभव साझा किये। विगत तीन दशक से अधिक समय में प्रदेश के पूर्ण साक्षरता के सफर में महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वंयसेवी संस्थाओं तथा स्वंयसेवकों ने अमूल्य योगदान दिया है। राज्य के शिक्षा सचिव राकेश कंवर 1990 में साक्षरता मिशन में साक्षरता स्वंयसेवक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

इस अवसर पर महापौर नगर निगम शिमला सुरेन्द्र चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद् और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# चबूतरा के बेघर हुए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे 8.70 लाख रुपये

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा कर नुक्सान का जायजा लिया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने गांव खैरी और इसके आस–पास के गांवों में बाढ़ एवं भू–स्खलन से हुये नुक्सान का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों को ढाढस बंधाया।

इसके बाद, मुख्यमंत्री गांव चबूतरा पहुंचे और वहां जमीन धंसने के कारण जमींदोज हुये मकानों तथा इसके आस–पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बेघर हुए परिवारों से भी बातचीत की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेघर हुए परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से 7–7 लाख रुपये देगी। इसके अलावा घर के लिए आवश्यक सामान खरीदने

के लिए भी 70–70 हजार रुपये दिए जाएंगे। स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह भी अपनी तरफ से एक–एक लाख रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी नुक्सान का आकलन किया जा रहा है तथा प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मानसून सीजन में प्रदेश भर में हुए भारी नुक्सान का वह स्वयं जाकर जायजा ले रहे हैं और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बेघर परिवारों को मकान निर्माण के लिए वन विभाग की सुरक्षित भूमि हस्तांतरित करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। चबूतरा के बाद मुख्यमंत्री ने कुठेड़ा में भी जन–समस्याएं सुनीं।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार अन्य पदाधिकारी, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर, अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।

# कर्मचारी हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सक्खू के निर्देशों के उपरान्त वित्त विभाग ने 6 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवायें (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में नियम 7ए को हटाने की अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इस तरह के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। नियम–कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शिमला में इस संबंध में मुख्यमंत्री से कई कर्मचारी संगठनों ने भेंट की तथा इस अधिसूचना को वापिस लेने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना है।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने कर्मचारियों को पुरानी पैंशन स्कीम बहाल की। इसके अलावा सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी।

# मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ की सहायता के लिए त्रिपुरा सरकार का आभार व्यक्त किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने त्रिपुरा राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष भारी बारिश से आयी आपदा से निपटने के लिए पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि आपदा राहत कोष में प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य चला रही है। उन्होंने प्रदेश की खुले मन से मदद करने वाले सभी अंशदाताओं का भी आभार व्यक्त किया।

# शिक्षा मंत्री ने सेब सीजन के दृष्टिगत सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और एचपीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला जिले में निरंतर हो रही

बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि अब तक केवल रोहडू सर्कल में ही 80 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। क्षेत्र में तीन प्रमुख जिला सड़कों और 227 ग्रामीण सड़कों सहित कुल 230 सड़कें प्रभावित हुई है। तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से एक पुल बह गया है। प्रभावित सड़कों में से अभी तक 203 को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष सड़कों को 4 सितंबर तक बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए 113 जेसीबी, रोबोट, डोजर और टिपर आदि मशीनें तैनात की गई हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनएच–705 को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि एनएच–707 पर यातायात बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इस सड़क मार्ग को भी 4 सितंबर तक बहाल कर दिया जाएगा।

एचपीएमसी के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत करवाया कि गुम्मा में 37 में से 31 सेब एकत्रीकरण केन्द्र और जुब्बल में 28 में से 25 सेब केन्द्र प्रभावित हुए हैं, जहां लगभग 80,000 सेब की क्रेटें रखी हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों और बार–बार हो रहे भूस्खलन के कारण सेब की ढुलाई प्रभावित हुई है और कई क्रेटें मलबे के नीचे दब गई हैं।

रोहित ठाकुर ने आश्वासन दिया कि सेब के सुचारु परिवहन के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने और 178 करोड़ रुपये के पीडीएनए फंड का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि के लिए नए अनुमान तैयार कर भेजने को भी कहा। उन्होंने समयबद्ध तरीके से निविदाएं जारी करने और कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग शिमला क्षेत्र के मुख्य अभियंता सुरेश कपूर, राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला क्षेत्र के प्रमुख अभियंता अजय कपूर, एचपीएमसी के महा प्रबन्धक सन्नी शर्मा भी बैठक में उपस्थित थे।

# मणिमहेश तीर्थयात्रियों के लिए चलाया गया बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न

**शिमला/शैल।** चंबा जिला प्रशासन द्वारा भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है।

इस क्रम में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर एमआई–17 से भरमौर से चंबा के लिए चार उड़ानों में 64 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इसअभियान में सुरक्षित निकाले गये सभी तीर्थयात्रियों को चंबा से नियमित अंतराल पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों के लिए निःशुल्क भेज दिया गया है। इसके साथ ही, दो शव भी भरमौर से चंबा लाए गए। दो दिन की अवधि के दौरान कुल 588 व्यक्तियों को भरमौर से चंबा तक एयरलिफ्ट किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सफलतापूर्वक चलाए गए बचाव अभियान के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चंबा पुलिस, होमगार्ड, गैर सरकारी संगठनों और लोगों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चंबा के लोगों ने **'अतिथि देवो भवः'** की भावना का परिचय दिया। मानवता का परिचय देते हुए लोगों ने भरमौर और रास्ते में लोगों के लिए लंगर का आयोजन किया।

मुख्यमंत्री ने इस अभियान का नेतृत्व कर रहे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की भी सराहना की। राजस्व मंत्री तीर्थयात्रियों की सफलतापूर्वक वापसी सुनिश्चित करने के लिए कई दिनों से भरमौर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी स्वेच्छा से चंबा से पैदल चलकर भरमौर पहुंचे और प्रत्येक फंसे हुए यात्री को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ लोगों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा कर रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

# प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार ने राज्य से लेकर केन्द्र सरकार की नीयत और नीति पर उठाये सवाल

**शिमला/शैल।** प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार को एक अतुल शर्मा ने यह कहकर चुनौती दी है कि यह सेवा विस्तार भारत सरकार के क्रामिक विभाग द्वारा अक्तूबर 2024 में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अधिसूचित दिशा निर्देशों की खुली उल्लंघना है। अक्तूबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार यदि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कोई संवेदनशील नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को कोई सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती चाहे दर्ज हुआ मामला किसी भी स्टेज पर क्यों न हो। स्मरणीय है कि जब प्रबोध सक्सेना भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे तब तत्कालीन वित्त मंत्री के खिलाफ आई.एन.एक्स मीडिया को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था और उसमें प्रबोध सक्सेना भी एक सह अभियुक्त थे। यह मामला अब संबंधित सी.बी.आई. की अदालत में विचाराधीन चल रहा है। अतुल शर्मा ने इस मामले का सारा रिकॉर्ड अपनी याचिका में संलग्न करके उच्च न्यायालय के संज्ञान में ला दिया है। उच्च न्यायालय में यह मामला अब 22 सितम्बर को फैसले के लिये लगा है। इस मामले में प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार सबको पार्टी बनाया गया है। सभी ने अपना-अपना पक्ष अदालत के सामने रख दिया है। इस रखे गये रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रबोध सक्सेना को एक वर्ष का सेवा विस्तार देने का आग्रह यह कहकर किया था कि राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सक्सेना पर आधारित है जो उनके बिना लटक जायेगा। भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री से एक वर्ष के सेवा विस्तार का आग्रह प्राप्त हुआ था लेकिन नियमों के अनुसार छः माह का ही सेवा विस्तार दिया जा सकता था। इससे अधिक का सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान सेवा विस्तार 30 सितम्बर को समाप्त हो रहा है। सबकी निगाहें उच्च न्यायालय के फैसले पर लगी है कि वह अक्तूबर 2024 को अधिसूचित दिशा निर्देशों की अवमानना पर क्या फैसला देते हैं।

प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार पर सरकार के उस दावे पर सबकी निगाहें लगी हुई है जिसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स का प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया गया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 31 अक्तूबर 1997 से एक इनाम योजना अधिसूचित है इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि भ्रष्टाचार पर आने वाली हर शिकायत की एक माह के भीतर प्रारंभिक जांच की जायेगी और शिकायत के सही पाये जाने पर शिकायतकर्ता को 15% ईनाम राशि का भुगतान कर दिया जायेगा तथा नियमित जांच आदेशित की जायेगी। 31 अक्तूबर 1997 से आज तक जितनी सरकारें आयी हैं किसी ने भी इस योजना को वापस नहीं लिया है और न ही आंकड़े जारी किये हैं कि इस योजना के तहत कितनी शिकायतें आयी और कितनी की जांच की गयी। विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिये थे कि वह विलेज कामन लैण्ड की सुरक्षा के लिये कड़े कदम उठाये और इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय को समय-समय पर सूचित करें। हिमाचल प्रदेश के नादौन में एक लाख कनाल से ज्यादा की विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच हो चुकी है बहुत सारे प्रभावशाली लोग इस खरीद बेच के लाभार्थी हैं। परन्तु आज तक भ्रष्टाचार के इस सबसे बड़े प्रमाणिक मुद्दे पर प्रदेश के एक भी मुख्य सचिव की नजर नहीं गयी है सारी सरकारें भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर आज तक खामोश रही है।

इस वस्तुस्थिति में यदि आई.एन. एक्स. मीडिया मामले में पी चिदम्बरम के साथ सहअभियुक्त रहे प्रबोध सक्सेना को व्यवस्था परिवर्तन के साये तले और भी सेवा विस्तार मिल जाये तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये। क्योंकि जिस भारत सरकार ने अपनी ही अधिसूचना को नजरअन्दाज करते हुये मुख्यमन्त्री के आग्रह को स्वीकार कर लिया उसकी नीयत और नीति को लेकर क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इस सेवा विस्तार के मुद्दे ने न केवल सरकार बल्कि पूरी कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं।

**यह है Court Proceeding**

Learned Additional Solicitor General of India has referred to additional reply filed by the Union of India in CWPIL No. 26 of 2025 that in view of Rule 16(1) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) Rules, 1958, a request had been made by the Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh for recommending the grant of extension in service to respondent No. 3, who was serving as Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. for a period of one year. Full justification had been given for his services for executing various projects in the State in public interest. Resultantly, the Competent Authority had granted the extension to the serving Chief Secretary for a period of six months, which was in consonance with the Rules.

2. The record has been produced by the State in a sealed cover regarding the communications. We have gone through the same and it is re-sealed and retained by this Court, which will remain in the custody of Registrar General.

3. Learned Additional Solicitor General of India submits that due to the inclement weather, he could not come present and produce the record as such of the Union of India. Though, he is in possession of the same.

4. It is further submitted by him that there is a cap on the period of extension which is only six months and there can be no further extension beyond the said period in view of the mandatory provisions of the Rules.

5. Request has also been made for accommodation on behalf of learned Senior Counsel for respondent No. 3 in CWPIL No. 26 of 2025.

6. Keeping in view the request which was made for the extension and grant of benefit which has been granted only for a period of six months, apparently, on considering the merits as such and not for the period of one year as asked for and as per the mandate of the Rules, we defer the proceedings for 22.09.2025.

## सूचना एकत्रित की जा रही

.....पृष्ठ 1 का शेष

बचा जा सकता है लेकिन जिस जनता को इन सवालों से फर्क पड़ता है उसे कैसे चुप कराया जायेगा क्योंकि उसके सामने तो हर सवाल खुली किताब की तरह है। आज सरकार ने निकाय चुनाव दो वर्ष के लिये ओ.बी.सी. आरक्षण के नाम पर टाल दिये हैं। संभव है कि पंचायत चुनावों को भी आपदा अधिनियम लागू होने के कारण टालने का आधार बन पाये। इस तरह सरकार चुनावी परीक्षा से तो बच जायेगी और उसका कार्यकाल निकल जायेगा। लेकिन इस तरह से विधानसभा चुनावों के समय सरकार क्या करेगी? अभी जब निकाय और पंचायत चुनावों की परीक्षा से बचा जा सकता है तो फिर संगठन का गठन भी कुछ समय के लिये टाले रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

## क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

.....पृष्ठ 1 का शेष

क्योंकि राजनीतिक दबाव में ही बार-बार रिटैन्शन पॉलिसीयां लायी गयी थी जिनका नुकसान प्रदेश भुगत रहा है।

## यह है नियुक्ति आदेश

Himachal Pradesh State Pollution Control Board
"Him Parivesh", Phase-III, New Shimla -171009
Phone No. 0177-2673766 & 2673032

No. PCB/Estt./Office Order/Vol.-X/2024/-8840-8990 Dated: 04.09.2025

**OFFICE ORDER**

Sh. Parveen Chander Gupta, Chief Environmental Engineer, presently working on secondment basis as Additional Director in the Department of Environment Science, Technology & Climate Change holding additional charge HPSPCB Regional Office, Baddi will perform the duties of Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board with immediate effect till the appointment of regular incumbent.

By order
(Kamlesh Kumar Pant, IAS)
Chairman, HPSPCB.
(Vide e office-Note#312)

Endst. No./ As above/- 8840-8990 Dated: 04.09.2025

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister to the Govt. of H.P., Shimla.
2. The Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Additional Chief Secretary (EST&CC) to the Govt. of Himachal Pradesh.
4. The Secretary (Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh with the request to appoint regular Member Secretary in the State Board.
5. All the Additional Chief Secretaries, Pr. Secretaries & Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
6. All the Heads of Department in Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
8. All the Managing Director of the Board and Corporation in Himachal Pradesh.
9. All the Member Secretary of the Central and State Pollution Control Boards & Committees.
10. The Director of Environment Science, Technology & Climate Change Shimla.
11. The Controller (F&A), Department of Personnel, HP Secretariat, Shimla.
12. The Chief Scientific Officer, HPSPCB Head Office, Shimla.
13. All the Divisional Heads of HPSPCB Head Office, Shimla.
14. All the Regional Officer(s) & Laboratory Incharge(s) of HPSPCB.
15. The PS to Chairman/Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board.
16. Guard/Personal File.

Signed by
Vinod Kumar Gautam
Date: 04-09-2025 19:35:52
(Vinod Kumar Gautam, HPF&AS)
Assistant Controller
H.P. State Pollution Control Board